

Prof- N. Ram
Assistant Professor
DEPT OF ECONOMICS
R.D.R. College Maharaigons

T.D.C Part I ECONOMICS (Hons)
Paper II Indian Economy
Module 3 New Economic Reforms
नवीन आर्थिक सुधार

आर्थिक सुधारों का अर्थ एवं उद्देश्य

(Meaning and objectives of Economic Reforms)

भारत में नवीन आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारम्भ 1991 में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतिযোগिता की दृष्टि से स्तरों को बढ़ा देने के दृष्टिकोण से किया गया। (New Economic Reforms in India mean the policies introduced since 1991 with a view to improve the levels of efficiency, productivity, profitability and competitiveness in the economy) ये आर्थिक सुधार उदारीकरण (Liberalisation) निजीकरण (Privatisation) तथा वैश्वीकरण (Globalisation) की नीतियों पर आधारित हैं। अतः इसे हम LPG मॉडल (LPG model of growth) कहते हैं।

21 जून 1991 को सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार ने उदारीकरण की नीति (Policy of Liberalisation) पर आधारित कुछ आर्थिक सुधारों की घोषणा की जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आंतरिक एवं बाह्य विश्वास की स्थापना करना तथा आनावश्यक नियंत्रणों को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को अधिक उदार (Liberal) बनाना था। उदारीकरण की नीति पर आधारित इन आर्थिक सुधारों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

- (i) औद्योगिक उत्पादन की कुशलता एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिযোগिता की दृष्टि से बढ़ा करना।
- (ii) भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक धिक् उपयोग करना।
- (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना तथा उसके क्षेत्र को अधिक प्रतियोगिता से भरवाना तथा
- (iv) निजी क्षेत्र में सुधार लाना एवं इसे आधुनिक बनाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को अधिक प्रभावशाली तरीका से पूरी कर सके।

यहाँ स्मरणीय है कि आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) के नाम से पुकारते हैं।

आर्थिक सुधारों के पीछे तर्क अथवा आर्थिक सुधारों की आवश्यकता
Rationale behind Economic Reforms or Need for Economic Reforms

यहाँ प्रश्न उठता है कि देश में आर्थिक सुधारों की क्यों आवश्यकता पड़ी? वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1991 तक भारत द्वारा अपनायी गई आर्थिक नीतियाँ तीव्र आर्थिक विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। जिनके कारण इन नीतियों ने हमें कई आर्थिक संकटों की ओर धकेल दिया था। इसके बीच में महसूस किया गया कि सरकार

द्वारा अपनायी गई औद्योगिक लाइसेंस नीति (Industrial Licensing Policy) के अन्तर्गत 1956 ई. की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के अन्तर्गत लड़ी गयी। स्वयं ही कई औद्योगिक धाराले ने विदेशी सहायता (Foreign Assistance) पर कब्जा कर लिया था क्योंकि व्यावसायिक बैंक इन देशों में नहीं आता था। देखा गया है कि औद्योगिक धाराले ने कई आर्थिक क्रियाओं पर अपना स्वतंत्रतापूर्ण प्रभाव डाला था और व्यापार को बाधित करने वाले अवरोधों को हटाने के लिए दशक के अन्त में यह महसूस किया गया कि विदेशी सहायता के बिना कई मदों को सुरक्षित कर दिया उन्हें आयात किया जाने देकर विदेशी पूँजी तथा तकनीक के आगमन पर कई तरह से रोक लगाकर बाजार में चलाने वाले शक्तिशाली क्षेत्र के उपक्रमों को भी बढ़ावा देकर सरकार निजी क्षेत्र (Private Sector) के औद्योगिक कार्यकलापों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा रही थी। सरकार कोरा तथा केंपी आयात शुल्क लगाकर विदेशी व्यापार में बाधा डाल रही थी। 1980 में अपनायी गई औद्योगिक नीति तथा कुछ अन्य उपायों द्वारा आर्थिक विकास की दर में सुद्धि हो गई लेकिन अर्थव्यवस्था तथा भी संकट में ही थी क्योंकि हमारे आंतरिक एवं बाह्य ऋणों में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार के वित्तीय खाते (Fiscal Deficit) राजस्व खाते (Revenue Deficit) तथा वाह्य संतुलन - बालु खाते के खाते में तीनों ही खड़े हुए।

इस प्रकार सभी खातों के समीक्षित प्रभाव ने अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न कर दिया। 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने संकट में आता में भी का काम किया और खाड़ी देशों को किये हमारे निर्यात में तथा उन देशों से प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई रकमों में गंभीर कमी हो गई। आर्थिक संकट के कारण गैर निवासीयों ने भारत में अपने बैंक खाते बन्द करने प्रारंभ कर दिये तथा विदेशों से क्रेता मिलने प्रारंभ कर दी गयी। इन सबके कारण भुगतान संतुलन के खाते में अत्यधिक खड़े हुए तथा विदेशी निग्रिम कोष में गंभीर डिफिशिट आ गई। देश में अफसरशाही एवं गाली पाताशाही का जोलाभाजा पहले से ही था उसने और खड़े हो गई। इसी परिस्थितियों के चलते 1991 में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। :-

(1) अनावश्यक नियंत्रण (Unnecessary controls) :- 1991 के पूर्व औद्योगिक लाइसेंस विदेशी पूँजी एवं तकनीक के आगमन पर प्रतिबंध, उद्योगों के कार्यकलापों को सीमित करने, आयात कोरा एवं आयात शुल्क इत्यादि के रूप में जो अनावश्यक नियंत्रण लगाये गये थे उनको हटाने के लिए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। इन नियंत्रणों को कम करने का उद्देश्य उद्योगों एवं आंतरिक तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देकर विकास को तीव्र करना था।

(2) सरकार के खाते में खड़े (Increase in deficits of the government) :- 1981-82 तथा 1991-92 के बीच सरकार के वित्तीय खाते में गंभीर खड़े हुए। 1981-82 में वित्तीय खाते (G.D.P. का 5.4 प्रतिशत) था जो 1991-92

मिला सके।

(3) प्रतिकूल भुगतान संतुलन (Unfavourable Balance of payment)
1991 के पूर्व हमारा भुगतान संतुलन भी काफी प्रतिकूल हो गया था। 1980-81 में हमारा भुगतान संतुलन का घाटा 2.214 करोड़ रुपये था जो 1990-91 में बढ़कर 17.361 करोड़ रुपये हो गया। इसको पूरा करने के लिए सरकार को विदेशी तहकों का सहारा लेना पड़ा। इसके कलस्वरूप हमारे विदेशी तहकों को 1980-81 में G.D.P के 12 प्रतिशत थे वे 1990-91 में बढ़कर G.D.P के 25 प्रतिशत हो गये। अतः प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करने के लिए आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी।

(5) मूल्यों में वृद्धि (Rise in prices) :- 1971 से 1991 के दौरान सरकार ने कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में काफी व्यय किया। कल्याणकारी व्यय में वृद्धि होने से हमारे गैर विकासोन्मुख व्ययों में भी भारी वृद्धि हुई। दूसरी ओर उत्पादन में प्राप्त वृद्धि नहीं होने के कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई जिसको नियंत्रित करने के लिए भी आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई।

(1) सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता (Inefficiency on the public sector) 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता प्रकट होनी लगी थी।